पटना उच्च न्यायालय में
आपराधिक विविध संख्या ४७२९६ वर्ष २०१५

थाना– औरंगाबाद से उत्पन्न शिकायत मामला संख्या २६२ वर्ष २०१४ जिला औरंगाबाद

= =

उमेश्वर दुबे पुत्र स्वर्गीय किशोर दूबे निवासी करा टोला दूबे बीघा, थाना ओबरा, जिला– औरंगाबाद

..................याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. कृष्ण विजय दूबे पुत्र स्वर्गीय सतरंजन दूबे
3. सुरेंद्र सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह
4. विनय सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह
5. इंद्रदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय बलदेव सिंह
6. अभय सिंह पुत्र दिगंबर सिंह सभी ग्राम० करा टोला के निवासी हैं। दुबे बीघा, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद

.... विपरीत पक्ष/पक्षों

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश सिंह, अधिवक्ता
ओ. पी. संख्या 2 से 6 के लिए		
राज्य के लिए	:	श्री नित्यानंद, एपीपी

याचिका – उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत माननीय एसडीजेएम (SDJM) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 379 और 504 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया।

निर्णय –

- मजिस्ट्रेट ने एक गंभीर त्रुटि की, जब उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश एक अन्य पुलिस अधिकारी को दिया, जबकि आरोपी स्वयं एक पुलिस अधिकारी था और याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में उसे अभियुक्त बनाया था। (पैरा 7)

- विवादित आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है। साथ ही, मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अध्याय XV** के तहत नवीन आदेश कानून के अनुसार और गुण–दोष के आधार पर पारित करें, बिना इस आदेश से प्रभावित हुए। (पैरा 7)

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

= =

कोरमः माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ता और राज्य के लिए ए पी पी श्री नित्यानंद को सुना

2. ओ. पी. संख्या 2 से 6 तक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. यह तात्कालिक आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सी आर पी सी') की धारा ४८२ के तहत दायर की गई है, जिसमें शिकायत मामला संख्या 262/२०१४ में पारित 09.04.2015 के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एस डी जे एम, दाउदनगर, औरंगाबाद ने ओ पी संख्या २ से ६ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (संक्षेप ओए ई पी सी) की धारा ३२३ और ५०४ के अंतर्गत अपराधों के अतिरिक्त ओ पी संख्या २ के विरुद्ध आई पी सी की धारा ३७९ के अंतर्गत अपराध का भी संज्ञान लिया है।

4. शुरुआत में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कृष्ण प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि इस न्यायालय द्वारा बुलाए गए एलसीआर को प्राप्त नहीं किया गया है, लेकिन तथापि, शिकायत वाद संख्या 262/2014 के प्रासंगिक आदेश पत्र इस याचिका के साथ दायर किए गए हैं और ये याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्न को देखते हुए इस मामले को तय करने के लिए पर्याप्त हैं।

5. आदेश का विरोध करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कार्यवाही किए जाने के बावजूद ओबरा पीएस के तत्कालीन एसएचओ और ओबरा सर्किल के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर और विद्वान मजिस्ट्रेट सहित नौ व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। याचिकाकर्ता की शिकायत पर दिनांक 22.10.2014 के आदेश द्वारा एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया कि क्या आरोपी अनिल कुमार चौधरी, तत्कालीन सर्कल अधिकारी और ओबरा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एस. एच. ओ. प्रवीण कुमार का कथित कार्य निजी क्षमता में किया गया था या एक लोक सेवक की हैसियत से किया गया था जो की कोई कानूनी आदेश नहीं था। यह कानून की स्थिर स्थिति है कि एक शिकायत पर मजिस्ट्रेट या तो मामले की जांच स्वयं कर सकता है या पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकता है और उक्त दो तरीकों में से किसी को भी उसके द्वारा चुना जाना है लेकिन वह एक साथ दोनों तरीकों का सहारा नहीं ले

सकता है। इस दलील के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील ने **फुलेना प्रसाद बनाम** के मामले में पारित इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। **राज्य ने (2002)** में बिहार और अन्य की रिपोर्ट **4 पी. एल. जे. आर. 232** और पैरा नं. इस निर्णय के 6 और 7, जिन पर निर्भरता रखी गई है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः .

> "6. अतः यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत की प्राप्ति होने पर जो धारा 192 (1) सी आर पी सी के तहत सौंपी गई थी, स्वयं मामले की जांच करने का तरीका चुना, लेकिन एस. ए. पर शिकायतकर्ता का बयान और चार और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने पुलिस से कथित घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसमें प्रभावित पीड़ित की तलाश करने का निर्देश दिया गया था। इसका मतलब है कि विद्वान एस डी जे एम ने धारा 202 करोड़ के तहत निर्धारित दोनों तरीकों का सहारा लिया जो की है की *"या तो स्वयं मामले की जांच करना या सीधे जांच करना।"* मेरी राय में, दोनों तरीकों का सहारा लेने में सीखी गई एस जे डी एम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं है और धारा 202 द्वारा अनुमेय नहीं है– जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि मजिस्ट्रेट *"या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी या पटना उच्च न्यायालय सी. आर. द्वारा जांच करने का निर्देश देगा।उसे जिसे वह उचित और उचित समझता है।*
>
> "या" शब्द के उपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में से किसी एक विधि को चुनना होगा। मैं विरोधी पक्षों की ओर से की गई इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पीड़ित लड़के की तलाशी लेना आवश्यक समझा और इसलिए, पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देकर उसने कोई त्रुटियां नहीं की है।यदि मजिस्ट्रेट ने केवल पीड़ित की खोज के संबंध में पुलिस की मदद ली होती तो मामला अलग होता, लेकिन इस मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश (जवाबी–

हलफनामे की अनुलग्नक–ए श्रृंखला) जिसके द्वारा उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने पीड़ित की खोज के निर्देश के साथ कथित घटना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को आदेश दिया था।इसलिए यह स्पष्ट है कि उसने पुलिस को केवल पीड़ित लड़के की तलाश करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने पुलिस को कथित घटना के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। विद्वान एस जे डी एम द्वारा पारित दिनांक 7.4.99 पारित आक्षेपित आदेश में धारा 203 सीआरपीसी के तहत शिकायत को खारिज कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सीआरपीसी पुनरीक्षण संख्या 106/99 में दिनांक 31.7.99 को पारित अपने आदेश में की है । इसकी पुष्टि विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सी आर पी सी एम पुनरीक्षण सं. 106/99 में दिनांक ३१।७।९९ को पारित अपने आदेश में की है, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज करते समय उसने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखा कि शिकायतकर्ता ने खुद अपने पुत्र को गुप्त रूप से रखा था और भूमि विवाद के कारण विरोधी पक्षों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। यह सच है कि आदेश की समापन पंक्ति में विद्वान एस जे डी एम ने उल्लेख किया है कि तथ्यों पर विचार करते हुए . और मामले की परिस्थितियों, शिकायतकर्ता द्वारा धारा 202 सी आर पी सी के तहत प्रस्तुत साक्ष्य और पुलिस द्वारा प्रस्तुत शिकायत को खारिज कर दिया जाता है लेकिन फिर पूरे आदेश को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत को खारिज करने के लिए मुख्य विचार पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट थी।

यह केवल इतना ही नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०२ द्वारा प्रदान किए गए दोनों विकल्पों को अपनाया। सी आर पी सी कानून के

प्रावधान के खिलाफ, पुलिस को जांच करने का निर्देश देने वाला उनका आदेश भी एक त्रुटि से ग्रस्त है।शिकायत याचिका में ही याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि पुलिस आरोपी व्यक्तियों के साथ मिली हुई है। ऐसी स्थिति में पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देना उचित नहीं था।

7. वर्तमान मामले में मैं पाता हूं कि धारा 202 सी आर पी सी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है और विद्वान एस जे डी एम गोपालगंज द्वारा मामले की जांच करने के बाद पुलिस द्वारा जांच का निर्देश देना कानून के अनुसार नहीं है। यह एक उपयुक्त मामला है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 सी आर पी सी के तहत अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है।"

विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत के माध्यम से आरोप लगाया जाता है तो ऐसी शिकायत को अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ संभाला जाना चाहिए और अभियुक्त पुलिस अधिकारी या उसके वरिष्ठ से रिपोर्ट मांगना या पुलिस द्वारा जाँच करने का आदेश देना अनुचित होगा और इस तरह के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं जाँच की जानी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील ने **राजेश्वर यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2004) 2 पीएलजेआर 699** में पारित इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है

6. राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री नित्यानंद ने इस याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है, हालांकि धारा २०० के तहत कार्यवाही शुरू करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सर्कल अधिकारी और ओबरा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एस. एच. ओ. के खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन विवादित आदेश पारित करते समय, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से शिकायत के साथ–साथ जांच गवाहों के बयानों पर भी भरोसा रखा, इसलिए, आदेश में कोई अवैधता नहीं है और इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है।

7. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश का अवलोकन किया।इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जांच के संबंध में लिए गए पहले आधार में कोई सार नहीं मिलता है, जिसे पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया था क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 की उप–धारा (1) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां शिकायत अदालत द्वारा नहीं की गई है, तब तक जांच के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता और गवाहों, यदि कोई मौजूद हैं, से सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शपथ पर जांच नहीं की जाती है और वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि शिकायत अदालत द्वारा दायर नहीं की गई थी, बल्कि यह एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी और विद्वान मजिस्ट्रेट ने चार जांच गवाहों की जांच के बाद दो अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में जांच का निर्देश देने का आदेश पारित किया, जिनमें शिकायतकर्ता शामिल थे, इसलिए, उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा **फुलेना प्रसाद (उपरोक्त)** के निर्णय में निर्धारित सिद्धांत याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है क्योंकि मजिस्ट्रेट के लिए शिकायतकर्ता और उसके वर्तमान गवाहों से पूछताछ करना अनिवार्य है जहां शिकायत किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच के लिए सी आर पी सी की धारा २०२ के तहत निर्देश पारित करने से पहले अदालत द्वारा नहीं की गई है।लेकिन फिर भी, विद्वान मजिस्ट्रेट ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच करने का आदेश देकर एक गंभीर त्रुटि की, जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोपी बनाया था और यह इस न्यायालय द्वारा **राजेश्वर यादव (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का उल्लंघन था। और आदेश पारित करने से पहले निचली अदालत को अप पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, दाउदनगर के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जो विवादित आदेश पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट को प्रभावित किया हो सकता है और इस कारण से, विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है और विद्वान मजिस्ट्रेट को योग्यता के अनुसार और इस आदेश से पूर्वाग्रहित हुए बिना कानून के अनुसार अध्याय XV के तहत एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

8. नतीजतन, तत्काल आपराधिक विविध याचिका की स्वीकार की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।